

सरकार ने CAA के तहत नागरिकता देना शुरू किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने पश्चिमी बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में [नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2024](#) के तहत नागरिकता प्रदान करना शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- 15 मई को, केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नई दिल्ली में उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण-पत्र का प्रारंभिक बैच प्रस्तुत किया गया, जो दिल्ली में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित **नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024** के जारी होने के बाद किया गया।
- गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को जारी नागरिकता संशोधन नियम, 2024 ने **CAA के कार्यान्वयन** का रास्ता साफ कर दिया है, जैसा **वर्ष 2019 में संसद द्वारा अनुमोदित** किया गया था।
 - दश-नरिदेशों के अनुसार, **पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समूहों के प्रवासी** पूर्वव्यापी प्रभाव से CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- CAA- 2019 के संशोधन** के तहत, जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुँचे थे और जिन्हें अपने देश में **"धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था या धार्मिक उत्पीड़न की आशंका थी"** वे नए कानून के तहत नागरिकता के लिये पात्र हो गए।
 - इन प्रवासियों को **छह वर्ष के भीतर त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान** की जाएगी। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीकरण/नागरिकीकरण के लिये **नविस की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष** कर दिया।

What the rules state

Centre has implemented CAA, 4yrs after the law was passed, as it notified rules ahead of expected announcement of LS polls

THE 39-PAGE NOTIFICATION... of the Citizenship (Amendment) Rules, 2024

...STATES THAT AN APPLICANT WILL HAVE TO SUBMIT

- | | | |
|--|---|--|
| • Form VIII A, with affidavits verifying statements and character of applicant | • Declaration that they have adequate knowledge of a language specified in 8th schedule of Constitution | • Supporting papers like a passport, or identity document to show someone in lineage was a citizen of one of the three countries |
|--|---|--|

APPLICANT MUST ALSO PROVE

- 1 They entered India before December 31, 2014
- 2 The applicant or either of his parents was a citizen of Independent India

WHAT IS THE 2019 ACT?

CAA made people from Hindu, Sikh, Jain Buddhist, Christian and Parsi faiths who entered India from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizenship

